आरएनआर प्रमोद कोहली से पहले जे.

देविंदर सिंह- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य- प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपीनं. 2008 का 21197 और

2009 का सीडब्ल्यूपी 476

27 सितंबर 2010 भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226–पंजाब पुलिस नियम, 1934–आरआई। 9.18(2) - एक कांस्टेबल के खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट दर्ज - अनिवार्य सेवानिवृत्ति - चुनौती - ईमानदारी पर संदेह करने के कारण - एक आपराधिक मामले में संलिप्तता - विभागीय कार्यवाही शुरू - आपराधिक मामले में आरोपी के रूप में दर्ज नहीं - याचिकाकर्ता को विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त किया गया - प्रतिकूल टिप्पणियाँ किसी भी अन्य सामग्री से प्रमाणित नहीं - बिना किसी सबूत के अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश - क्षेत्राधिकार का रंगीन प्रयोग - याचिका की अनुमति, संदिग्ध सत्यनिष्ठा का प्रवेश और याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश रद्द कर दिया गया।

माना गया कि एफआईआर नंबर 4 दिनांक 3 जनवरी 2007 और विभागीय कार्यवाही याचिकाकर्ता की ईमानदारी पर संदेह करने का कारण हैं। जहां तक दक्षता आदि से संबंधित अन्य पहलुओं का सवाल है, शायद किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। एफआईआर और विभागीय कार्यवाही के अलावा किसी भी सामग्री का उल्लेख नहीं किया गया है। यहां तक कि ऐसी राय के कारणों को भी उत्तर में दर्ज या खुलासा नहीं किया गया है। आपराधिक कार्यवाही और विभागीय जांच के नतीजे को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता की सत्यनिष्ठा के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणियां किसी भी सामग्री से प्रमाणित नहीं होती हैं और इस प्रकार, उचित नहीं हैं।

(Para 12)

इसके अलावा, यह माना गया कि राय गैर-मौजूद सामग्री यानी बिना सबूत के तैयार की गई है, जैसा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के विवादित आदेश से स्पष्ट है, जिसमें 3 जनवरी की एफआईआर संख्या 4 का संदर्भ दिया गया है। 2007 और दो विभागीय पूछताछ। इन दोनों मामलों का परिणाम पहले ही देखा जा चुका है। इस प्रकार, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का कोई आधार मौजूद नहीं है और यह रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं होने का मामला है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश क्षेत्राधिकार का एक रंगीन अभ्यास है और इसे रद्द किया जा सकता है।

(पैरा 18 एवं 19

याचिकाकर्ताओं के वकील एके बूरा ।

आरएस कुंडू, अतिरिक्त।

उत्तरदाताओं के लिए एजी, हरियाणा ।

परमोद कोहली, जे.

(1) ये दो रिट याचिकाएं 26 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 की अवधि के लिए प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं - आदेश दिनांक 29 मई, 2008 (अनुलग्नक पी -3) 2008 के सीडब्ल्यूपी संख्या 21197 में और संचार दिनांक 24 दिसंबर, 2008 (अनुलग्नक पी-4) और अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिनांक 2 जनवरी, 2009 (अनुलग्नक पी-6) 2009 के सीडब्ल्यूपी संख्या 476 में।

(2) इन दो रिट याचिकाओं को दाखिल करने से जुड़े तथ्यों पर यहां संक्षेप में गौर किया गया है।

(3) याचिकाकर्ता को 12 दिसंबर, 1978 को जिला भिवानी में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। यह कहा गया है कि उनकी सेवा के 29 वर्षों के लंबे कार्यकाल में, उन्हें 31 प्रशस्ति प्रमाणपत्रों से सम्मानित किया गया है, जिसमें उनके खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट दर्ज की गई अवधि यानी 26 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 के दौरान दो प्रमाणपत्र शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने कहा है दिनांक 23 मई, 2007 को संचार के माध्यम से उनके सेवा रिकॉर्ड में प्रतिकूल रिपोर्ट रिकॉर्ड से अवगत कराया गया। याचिकाकर्ता ने उचित माध्यम से उपरोक्त प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ - अनुबंध पी-2 के माध्यम से एक अभ्यावेदन दिया,। यह अभ्यावेदन 29 मई, 2008 के मेमो (अनुलग्नक पी-3) द्वारा एक गैर-भाषी आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है, जो 2008 के सीडब्ल्यूपी संख्या 21197 में प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ चुनौती का विषय है। जबकि यह याचिका लंबित थी याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस (2009 के सीडब्ल्यूपी संख्या 476 के साथ अनुबंध पी-2) दिया गया है, जिसमें प्रस्ताव दिया गया है

हरियाणा राज्य पर लागू और समय-समय पर संशोधित पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 9.18 (2) के उप नियम (2) के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक हित में उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए। उनसे 15 दिन के भीतर अपना जवाब देने को कहा गया है. उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जवाब में, याचिकाकर्ता ने उचित माध्यम से एक विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया, - 2009 के सीडब्ल्यूपी संख्या 476 के साथ अनुबंध पी-3 के माध्यम से। पुलिस महानिदेशक, हरियाणा ने अपने आदेश दिनांक 23 दिसंबर, 2008 (2009 के सीडब्ल्यूपी संख्या 476 के साथ अनुलग्नक पी-4) द्वारा याचिकाकर्ता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया और इसे नियम के तहत अनुमोदन के लिए सरकार को भेज दिया। पंजाब पुलिस नियम, 1934 के 9.18(2) इस आदेश को याचिकाकर्ता को सूचित करने का निर्देश दिया गया था, - पत्र दिनांक 31 दिसंबर, 2008 (2009

के सीडब्ल्यूपीनंबर 476 के साथ अनुबंध पी-5)। नतीजतन, याचिकाकर्ता 31 दिसंबर, 2008 से 2 फरवरी, 2009 के बाद के आदेश (2009 के सीडब्ल्यूपी नंबर 476 के साथ अनुबंध पी -6) के तहत सेवानिवृत्त हो गया है । कारण बताओ नोटिस और अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश 2009 के सीडब्ल्यूपी संख्या 476 में चुनौती का विषय है।

(4) इन रिट याचिकाओं में प्रतिकूल रिपोर्ट और अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती देने के सामान्य आधार पेश किए गए हैं।

(5) यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता को नवंबर, 2006 के महीने में प्रभारी रेलवे पुलिस पोस्ट, भिवानी के रूप में तैनात किया गया था, जहां एक सूरज मल, हेड कांस्टेबल, बेल्ट नंबर 522, उसके अधीन काम कर रहा था। आरोप है कि सूरजमल ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे. याचिकाकर्ता ने अपनी अनुपस्थिति दर्ज की और इस कारण से वह याचिकाकर्ता का शत्रु बन गया। आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता 11 दिसंबर, 2006 से 12 दिसंबर, 2006 तक एक दिन की छुट्टी पर था और इस अवधि के दौरान, सूरज मल ने जय सिंह पुत्र सूरत सिंह, जाति सांसी को उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए उकसाया। याचिकाकर्ता. जय सिंह की शिकायत पर पुलिस स्टेशन, जीआरपी, हिसार में भारतीय दंड संहिता की धारा 344, 383 और 34 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 4 दिनांक 3 जनवरी, 2007 दर्ज की गई थी। सीआईए के एक इंस्पेक्टर ओम प्रकाश को इसकी जांच सौंपी गई। याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत की मांग की जिसे विद्वान सत्र न्यायाधीश, भिवानी ने मंजूर कर लिया। सीआरपीसी की धारा 439(2) के तहत याचिका। अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए की गई पीसी को हाईकोर्ट ने वापस लिया हुआ मानते हुए खारिज कर दिया। जांच के बाद, सीआरपीसी की धारा 173 के तहत अदालत को सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट में याचिकाकर्ता को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। पी.सी., न ही उन्हें न्यायालय द्वारा तलब किया गया। यह भी कहा गया है कि इसके साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिये गये थे

याचिकाकर्ता. जांच करने वाले डीएसपी रणवीर सिंह ने याचिकाकर्ता को निर्दोष पाया। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनकी एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणियां गलत हैं और किसी सामग्री पर आधारित नहीं हैं। 23 मई, 2007 के ज्ञापन के अवलोकन से, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी का संकेत दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि एफआईआर संख्या 4 दिनांक 3 जनवरी, 2007 का संदर्भ दिया गया है, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज किया गया था। आगे याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई दो विभागीय जांचों का संदर्भ दिया गया है और याचिकाकर्ता को इन दोषों को दूर करने की सलाह दी गई है। याचिकाकर्ता ने अपनी प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसे 29 मई, 2008 के ज्ञापन के माध्यम से खारिज कर दिया गया। अभ्यावेदन की अस्वीकृति का आदेश पूरी तरह से निरर्थक है।

"बिना किसी गुण के" के अलावा कोई भी कारण सूचित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर में कभी आरोपी नहीं बनाया गया। अदालत में पेश आरोप पत्र में, यहां तक कि अन्य आरोपियों, जिनके खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवानी की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था, को 6 दिसंबर, 2008 के फैसले द्वारा बरी कर दिया गया था। यहां तक कि विभागीय कार्यवाही में भी, याचिकाकर्ता जांच अधिकारी द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया। दंड प्राधिकारी ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट से असहमत होते हुए, याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें स्थायी प्रभाव से पांच भविष्य की वेतन वृद्धि रोकने का दंड देने का प्रस्ताव किया गया। याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया। हालाँकि, दंड प्राधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के तहत स्थायी प्रभाव से एक भविष्य की वेतन वृद्धि को रोकने की सजा दी । सजा के पुरस्कार से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 के समक्ष अपील दायर की और सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता और रिकॉर्ड पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता की अपील स्वीकार कर ली गई और एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि को दिनांक 16 जुलाई, 2008 के आदेश के तहत अनुलग्नक पी-5 सीडब्ल्यूपीएनओ के साथ) .21197 of2008). रोकने की सजा को निंदा की सजा में बदल दिया गया, -

(6) अपने प्रतिकूल एसीआर के खिलाफ याचिकाकर्ता की एक शिकायत यह है कि प्रतिकूल रिपोर्ट 12 दिसंबर, 1985 के सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दर्ज की गई है। उत्तरदाताओं द्वारा पारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश भी पूरी तरह से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आधारित है। ,

(7) दोनों रिट याचिकाओं के जवाब में दलील लगभग सामान्य है. इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि याचिकाकर्ता को 3 जनवरी, 2007 की एफआईआर संख्या 4 में मुकदमे के लिए नहीं भेजा गया था, यह माना गया कि याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया था जांच अधिकारी द्वारा उसके विरूद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की गई हालाँकि, याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई को उचित ठहराने की दृष्टि से, यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता पर दूसरे मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था। एक मामले में, उसका वार्षिक 9 जनवरी, 2008 के ज्ञापन के माध्यम से वेतन वृद्धि स्थायी प्रभाव से रोक दी गई थी। एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर की गई शिकायत का भी संदर्भ दिया गया है।।। याचिकाकर्ता के खिलाफ नारायण दत्त पुत्र गणपत राम ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने आभूषणों की चोरी की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और । आरोपी को भागने में मदद की और इस प्रकार, उसने सरकार/रेलवे पुलिस, हरियाणा। उसकी छवि को धूमिल किया है

(8) 26 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2006 की अवधि के लिए अनुबंध पी-1 के माध्यम से याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: -

1) ईमानदारी-संदिग्ध।

एल (3) नैतिक साहस और अनाचारों को उजागर करने की तत्परताअधीनस्थों की कमी।

(4) जनता के साथ निष्पक्ष व्यवहार और जनता तक पहुंच के लिए प्रतिष्ठा : उचित नहीं।

k (9) व्यक्तित्व एवं पहल" उचित नहीं है।

(10) कमांड की शक्ति: ढीला.

(11) जांच के आधुनिक तरीकों और आधुनिक पुलिस तरीकों में रुचि नहीं है।

(12) निवारक और जासूसी क्षमता: कोई उचित नहीं।

(13) (13) आपराधिक कानून और प्रक्रिया का कार्य अनुभव: कमी

अनुभव।

(14) विश्वसनीयता: विश्वसनीय नहीं.

(16) क्या अधिकारी/अधिकारी मुख्यालय पर रहते हैं? या नहीं कार्यालय समय के बाद ज : नहीं रहता/रहता है।

(19) दोष, यदि कोई हो, और क्या उन्हें किसी पत्र के माध्यम से उनके ध्यान में लाया गया था: एफआईआर संख्या 4 दिनांक 3 जनवरी, 2007, यू/एस 3 84/342/34आईपीसी जीआरपीएस में संलिप्तता के कारण निलंबित कर दिया गया था। हिसार, अन्य के साथ और विभागीय जांच ज्ञापन संख्या 1567-78/ए-1, दिनांक 9 जनवरी, 2007 के माध्यम से शुरू की गई थी। विभागीय जांच ज्ञापन संख्या 1599-605/ए, दिनांक 9 जनवरी, 2007 के माध्यम से शुरू की गई थी । गैर समय पर शिकायत दर्ज करना।सामान्य टिप्पणियाँ: पुलिस विभाग में अक्षम कर्मचारी।एएसआई देविन्दसीआर सिंह क्रमांक 607//जीआरपी को उपरोक्त प्रतिकूल टिप्पणियों से अवगत कराया जाए और इन दोषों को दूर करने का निर्देश दिया जाए। इसके साथ संलग्न दूसरी प्रति पर कर्मचारी के तारीख सहित हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएं और उसे पावती के रूप में इस कार्यालय को भेजा जाए।

एसडी/

पुलिस महानिदेशक, रेलवे एवं तकनीकी सेवाएं, हरियाणा, मोगी नंद, पंचकुला।

(9) उपरोक्त प्रतिकूल प्रविष्टियों को संप्रेषित करते समय पत्र के अंतिम पैराग्राफ में यह भी उल्लेख किया गया था कि अधिकारी को इन दोषों को दूर करने हेतु निर्देशित किया जाये। ऐसा भी प्रतीत होता है कि विभिन्न कॉलमों में प्रतिकूल टिप्पणियाँ, मुख्य रूप से, एफआईआर संख्या 4, दिनांक 3 जनवरी, 2007 और याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच पर आधारित हैं। अन्यथा याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने के लिए कोई अन्य सामग्री संदर्भित नहीं की गई है। याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे एवं तकनीकी सेवाएं हरियाणा द्वारा एक अस्पष्ट एवं गैर-स्पष्ट आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। अस्वीकृति आदेश दिनांक 29 मई, 2008 (अनुलग्नक पी-3) इस प्रकार है:- मैंने 26 अप्रैल, 2006 से 31

मार्च, 2007 की अवधि के लिए उनके एसीआर में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ एएसआई दविंदर सिंह संख्या 607/जीआरपी द्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधित्व, रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्डों को देखा है। उनका प्रतिनिधित्व किया गया है किसी भी योग्यता से रहित होने पर विचार किया गया और अस्वीकार कर दिया गया। तदनुसार प्रतिनिधित्वकर्ता को सूचित किया जाए।

(एसडी.) . .

(केके मिश्रा)।

पुलिस महानिरीक्षक/∗ रेलवे, और तकनीकी सेवाएँ हरियाणा। मोगी नंद. पंचकुला।"

(10) याचिकाकर्ता ने एफआईआर नंबर 4, दिनांक 3 जनवरी, 2007 के अनुसार दायर आपराधिक मामले संख्या 143-1/08 में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवानी द्वारा पारित 16 दिसंबर, 2008 के आदेश को रिकॉर्ड पर रखा है, जिसमें याचिकाकर्ता था प्रारंभ में शामिल थे। याचिकाकर्ता को आरोपी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। यहां तक कि आरोपी बनाए गए दो लोगों को भी बरी कर दिया गया है। यह भी सर्वमान्य तथ्य है कि विभागीय जांच में भी याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी का आधार ही गायब हो जाता है।

(11) उपरोक्त के अलावा, याचिकाकर्ता ने 12 दिसंबर, 1985 के सरकारी निर्देशों पर भी भरोसा किया है। संदिग्ध सत्यनिष्ठा के संबंध में रिपोर्टिंग से संबंधित प्रासंगिक निर्देशों के लिए आवश्यक है कि रिपोर्टिंग अधिकारी को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि क्या अधिकारी पर भ्रष्टाचार का संदेह है या ऐसा माना जाता है। भ्रष्ट और यह राय आम तौर पर उन कारणों से तैयार की जानी चाहिए जो रिपोर्टिंग अधिकारी के पास हो सकते हैं।

(12) ऊपर देखी गई प्रतिकूल रिपोर्टों से, यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि एफआईआर नंबर 4, दिनांक 3 जनवरी, 2007 और विभागीय कार्यवाही याचिकाकर्ता की ईमानदारी पर संदेह करने का कारण हैं। जहां तक उसकी कार्यकुशलता आदि से संबंधित अन्य पहलुओं का संबंध है, संभवत: किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। एफआईआर और विभागीय कार्यवाही के अलावा किसी भी सामग्री का उल्लेख नहीं किया गया है। यहां तक कि ऐसी राय के कारणों को भी उत्तर में दर्ज या खुलासा नहीं किया गया है। आपराधिक कार्यवाही के नतीजे और ऊपर देखी गई विभागीय जांच के मद्देनजर, याचिकाकर्ता की सत्यनिष्ठा के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणियां किसी भी सामग्री से प्रमाणित नहीं होती हैं और इस प्रकार, उचित नहीं हैं।

(13) अपीलीय प्राधिकारी ने भी उस अभ्यावेदन को अस्वीकार करने का कोई कारण दर्ज करने की जहमत नहीं उठाई, जिसे बहुत ही अनौपचारिक तरीके से निपटाया गया है। जवाब में भी

याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन खारिज करने का कोई आधार नहीं बताया गया है. यह भी देखा गया है कि प्रतिकूल प्रविष्टियाँ संसूचित करते समय याचिकाकर्ता को उसकी कमियाँ दूर करने के लिए परामर्श देने का सुझाव दिया गया था। यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि किसी भी स्तर पर याचिकाकर्ता को परामर्श नहीं दिया गया या उसकी खामियों से अवगत नहीं कराया गया। इस प्रकार, सज़ा देने के बाद सलाह या परामर्श घोड़े के आगे गाड़ी लगाने के समान है।

(14) इस प्रकार, 23 मई, 2007 का आदेश (अनुलग्नक पी-1) यानी प्रतिकूल टिप्पणी कॉलम नंबर 1 "संदिग्ध" के संबंध में रद्द की जा सकती है। इस न्यायालय के लिए अन्य कॉलमों में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है। जिसमें याचिकाकर्ता की दक्षता आदि पर टिप्पणी की गई है। नतीजतन, पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे और तकनीकी सेवाएं, हरियाणा द्वारा दिनांक 29 मई, 2008 (अनुलग्नक पी-3) पारित आदेश भी याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को खारिज कर देता है।

(15) अब आते हैं 2009 की सिविल रिट याचिका संख्या 476 पर। उपरोक्त उल्लिखित प्रतिकूल टिप्पणियों, एफआईआर नंबर 4, दिनांक 3 जनवरी, 2007 और दो विभागीय जांचों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को दिनांक 24 दिसंबर, 2008 (अनुलग्नक पी -4) के आक्षेपित आदेश के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। एक विभागीय जांच में याचिकाकर्ता को एक वेतन वृद्धि अस्थायी प्रभाव से रोकने की सजा दी गई है, जबकि दूसरे विभाग की जांच में उसे एक वेतन वृद्धि स्थायी प्रभाव से रोकने की सजा दी गई है। दूसरी जांच गणपत राम के पुत्र नारायण दत्त की शिकायत पर की गई। जहां तक दूसरी जांच का सवाल है, याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी यानी पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे और तकनीकी सेवाएं, हरियाणा द्वारा 16 जुलाई, 2008 को पारित एक आदेश रिकॉर्ड में रखा है, जिसके तहत एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि को रोकने का जुर्माना लगाया गया है। स्थाई प्रभाव केवल निंदा तक सीमित कर दिया गया है। एफआईआर संख्या 4, दिनांक 3 जनवरी, 2007 के संबंध में, यह पहले ही देखा जा चुका है कि याचिकाकर्ता को आपराधिक मामले में चालान नहीं किया गया है और विभागीय जांच में दोषमुक्त नहीं किया गया है। यह चिंता का विषय है कि पुलिस महानिदेशक, रेलवे और तकनीकी सेवाएं, हरियाणा ने एक ऐसी सजा पर भरोसा किया जो अस्तित्व में नहीं है, अपीलीय प्राधिकारी ने एक वेतन वृद्धि को स्थायी प्रभाव से रोकने के दंड को निंदा में बदल दिया है। या तो अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को उनके संज्ञान में नहीं लाया गया या उन्होंने अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करते समय इसकी अनदेखी की है। किसी भी मामले में, केवल एक विभागीय जांच में अस्थायी प्रभाव से एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने की सजा के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश, किसी भी आधार पर उचित नहीं है।

(16) नाइकुंठ नाथ दास बनाम मुख्य जिला के मामले में । चिकित्सा अधिकारी (1), माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश की वैधता की जांच के लिए पांच सिद्धांत निर्धारित किए हैं । (टी) (f992)TscZ?299प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-“16. बैकुंठ नाथ दास

बनाम मुख्य जिला मामले में इस न्यायालय की तीन-जुगड़े पीठ । चिकित्सा अधिकारी ने निम्नलिखित पाँच सिद्धांत निर्धारित किए (एससीसी पृष्ठ 315 पैरा 34):-"(i) अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश कोई सज़ा नहीं है। इसका तात्पर्य कोई कलंक या दुर्व्यवहार का कोई संकेत नहीं है।

(ii) यह राय बनने पर कि सरकारी सेवक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देना लोकहित में है, सरकार द्वारा आदेश पारित किया जाना है। यह आदेश सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पारित किया गया है

(jii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई स्थान नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायिक जांच को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। हालांकि उच्च न्यायालय या यह न्यायालय अपीलीय अदालत के रूप में मामले की जांच नहीं करेगा, वे हस्तक्षेप कर सकते हैं यदि वे संतुष्ट हैं कि आदेश पारित किया गया है (ए) दुर्भावनापूर्ण है या (बी) कि यह बिना किसी सबूत पर आधारित है (सी) कि यह है मनमाना-इस अर्थ में कि कोई भी उचित व्यक्ति दी गई सामग्री पर अपेक्षित राय नहीं बनाएगा; संक्षेप में, यदि यह विकृत क्रम पाया जाता है।

(iv) सरकार (या समीक्षा समिति, जैसा भी मामला हो) को बाद के वर्षों के दौरान रिकॉर्ड और प्रदर्शन को अधिक महत्व देने के मामले में निर्णय लेने से पहले सेवा के पूरे रिकॉर्ड पर विचार करना होगा। इस प्रकार विचार किए जाने वाले रिकॉर्ड में स्वाभाविक रूप से गोपनीय रिकॉर्ड/चरित्र पंजिका में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह की प्रविष्टियां शामिल होंगी। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो ऐसी टिप्पणियों का महत्व खत्म हो जाता है, खासकर तब जब पदोन्नति योग्यता (चयन) पर आधारित हो, न कि वरिष्ठता पर।

(v) अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश किसी अदालत द्वारा केवल यह दिखाने पर रद्द नहीं किया जा सकता कि इसे बिना संचार के पारित करते समय प्रतिकूल टिप्पणियों को भी ध्यान में रखा गया था। वह परिस्थिति अपने आप में हस्तक्षेप का आधार नहीं हो सकती।"

(17) इस निर्णय को बाद के कई निर्णयों में दोहराया गया है, जिसमें गुर जुरात राज्य और अन्य बनाम सन उर्फ चुन्नीलाल शाह (2) का मामला भी शामिल है।

(IX) वर्तमान मामले में, राय गैर-मौजूद सामग्री यानी बिना सबूत के तैयार की गई है, जैसा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के विवादित आदेश से स्पष्ट है जिसमें एचआर नंबर, 4 दिनांक 3 जनवरी का संदर्भ दिया गया है। 2007 और दो विभागीय जाँच। इन दो मामलों के नतीजे पहले ही ऊपर देखे जा चुके हैं। इस प्रकार, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का कोई आधार मौजूद नहीं है और यह रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं होने का मामला है। सूर्यकांत चुन्नीलाल के मामले में (सुप्रा)। मैं उच्चतम न्यायालय को निम्नानुसार मानता हूं:- -

(X) यह फैसला बॉम्बे सिविल सेन आइसिस रूल्स के नियम 161 के तहत लिया गया. 1959. जो निम्नानुसार प्रदान करता है:"161.(1)(ए) इस नियम के अन्य खंडों में अन्यथा प्रदान किए जाने

के अलावा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अलावा किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख वह तारीख है जिस दिन वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करता है .

प्रदान किया-

(i)-(ii) * * * *

(III) मुझे अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद केवल सार्वजनिक आधार पर सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ सेवा में बनाए रखा जा सकता है जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।(एए) खंड (ए) में किसी बात के बावजूद:

(I) एक नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह इसकी राय में है, तो यह करेगा ऐसा करना जनहित में है। किसी भी सरकारी कर्मचारी, जिस पर खंड (ए) लागू होता है, को ऐसे नोटिस के बदले में कम से कम तीन महीने का नोटिस या तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है:

(1) यदि वह क्लास 1 या क्लास ॥ सेवा या पद पर है या किसी अवर्गीकृत राजपत्रित पद पर है, तो उसके लिए आयु-सीमा

(2) (1999) आई एससीसी 529 सीधी भर्ती का उद्देश्य जिसकी आयु 35 वर्ष से कम है, उस तिथि को या उसके बाद जिस दिन वह 50 वर्ष की आयु प्राप्त करता है और।

(2) यदि वह किसी अन्य सेवा या पद पर है तो आयु-सीमासीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए जिसकी आयु 40 वर्ष से कम है, उस तिथि को या उसके बाद जिस दिन वह 55 वर्ष की आयु प्राप्त करता है।

(II) कोई भी सरकारी प्रतिनिधि जिस पर खंड (ए) लागू होता है। नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम तीन महीने की लिखित सूचना देकर, 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएं, यदि वह श्रेणी । या श्रेणी ॥ सेवा या पद पर है या किसी अवर्गीकृत राजपत्रित पद पर है तो आयु- भर्ती के प्रयोजन के लिए सीमा 35 वर्ष से कम है और अन्य मामले में, 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद: बशर्ते कि यह नियुक्ति प्राधिकारी के लिए खुला होगा कि वह ऐसे सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने की अनुमति रोक दे जो निलंबित है, या जिसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही लंबित है या विचाराधीन है और जो इस उप-खंड के तहत सेवानिवृत्त होना चाहता है।(बी) एक सरकारी कर्मचारी "

(19) मेरा मानना है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश अधिकार क्षेत्र का एक रंगीन अभ्यास है और इसे रद्द किया जा सकता है।

(20) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों रिट याचिकाओं को निम्नलिखित निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाता है:-

1. एक संदिग्ध सत्यनिष्ठा की प्रविष्टि संसूचित की गई - दिनांकित पत्र के माध्यम से

23 मई. 2007 (सीडब्ल्यूपीनंबर 21197ऑफ2008 में अनुलग्नक पी-1) दिनांक 29 मई के आदेश के साथ। 2008 (अनुलग्नक पी-3) में अभ्यावेदन को उस हद तक खारिज कर दिया गया, जहां तक यह संदिग्ध सत्यनिष्ठा के प्रवेश से संबंधित है, इसे रद्द कर दिया गया है।

2. अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिनांक 2 जनवरी. 2009 (अनुलग्नक पी-6) 2009 के सीडब्ल्यूपी संख्या 476 में भी रद्द कर दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसमीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कैथल, हरियाणा